ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 66-68

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

भारतीय राष्ट्रवाद और डॉ0 अंबेडकर

डॉ0 शशिबाला

असि0 प्रो0– अर्थशास्त्र विभाग, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-24.07.2022, Revised-29.07.2022, Accepted-03.08.2022 E-mail:drshashibala09@gmail.com

सारांश:– ***"कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक रूप से एक ना हो"***
– डॉ0 अम्बेडकर

डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर की भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा विभिन्न उद्देश्यों के साथ शुरू हुई, जो समाज के सीमांत वर्ग के कल्याण की राशि थी। वह उन व्यक्तियों के लिए समानता और नागरिक अधिकार चाहते थे, जो हजारों वर्षों से उनसे वंचित थे। समाज के निचले तबके के उत्थान के बिना, एक राष्ट्र अपने समग्र विकास के लिए गति प्राप्त नहीं कर सकता है और वास्तविक अर्थों में उसकी ताकत नहीं हो सकती है। उन्हें अपने देश की महानता और पारंपरिक संस्कृति और इसलिए अपने देशवासियों की गरिमा पर पूरा भरोसा था। उनमें राष्ट्रवाद बाहरी वर्चस्व और आंतरिक उत्पीडन दोनों के विरोध के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने भारतीय लोगों के कल्याण की लापरवाही के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने तर्क दिया कि एक राष्ट्र एकजुट नहीं हो सकता और राष्ट्रीय भाईचारे की सराहना अछूत और यहां तक कि ऊंची जातियां भी नहीं कर सकतीं। ब्रिटिश सरकार कभी भी ऐसा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। उस उद्देश्य के लिए, इसे एक ऐसी सरकार की आवष्यकता थी, जो "लोगों की, लोगों के लिए, और लोगों द्वारा" हो, जो इसे संभव बनायेगी।

कुंजीभूत शब्द–भारतीय राष्ट्रवाद, सीमांत वर्ग, कल्याण, समानता, समग्र विकास, महानता, पारंपरिक संस्कृति, गरिमा, वर्चस्व।

ब्रिटिशकाल में राष्ट्रवाद, समाजवाद तथा आर्थिक स्वतंत्रता–डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने टिप्पणी की, "ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों के अधिकारों की बहाली के लिए उत्साह से काम नहीं किया और अछूतों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया।" जब तक भारत के नागरिकों ने राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं की और जब तक वह शक्ति भारतीय समाज के सामाजिक रूप से दबे हुए वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं हो जाती, तब तक सभी सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक अक्षमताओं को पूरी तरह से मिटाना संभव नहीं हो सकता है, जिसके तहत वह वर्ग पीड़ित था। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता के बिना, राष्ट्रवाद आंतरिक दासता, जबरन श्रम का एक तरीका बन जाता है, और गरीब दास वर्गो के लिए अत्याचार की व्यवस्था करता है। बाबासाहेब ने तर्क दिया कि "हमारे देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण मुददे को भूलना पूरी तरह से गलत है। यह कल्पना करना विनाषकारी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ अनिवार्य रूप से वास्तविक सर्वांगीण स्वतंत्रता है।

डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर नीति निर्माण में शामिल थे, एक बार 1947–51 के दौरान स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर एक कानून मंत्री के रूप में, और पहले वायसराय की परिशद के सदस्य के रूप में, श्रम, सिंचाई और बिजली विभागों के लिए जिम्मेदार थे। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यापक आर्थिक अध्ययन, सैद्धांतिक मुद्दों को भी ठोस आर्थिक समस्याओं के रूप में लिखा। वह एक ऐतिहासिक और विष्लेषणात्मक अध्ययन भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे।

आर्थिक नीति, और प्रशासन, प्रांतीय स्वायत्तता और भारतीय लोगों की समस्याओं, गरीबी , बेरोजगारी और असमानताओं, स्थिर कृषि और विकृत औद्योगीकरण के बारे में उनके विचार उत्कृष्ट थे। उनका दावा है कि 1– सामाजिक शोषण और अन्याय हर देश में प्रचलित थे और 2– राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं एक–दूसरे से जुड़ी हुई थी आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने इस तरह की दूरदर्शिता के साथ मुद्दों पर संपर्क किया और उनकी जांच की कि उनमें से कई का विश्लेषण और उपचार आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। उन्होंने एम0एस0सी0 "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास" पर उनकी थीसिस के लिए और उन्हें डी0एस0सी0 "रूपये की समस्या" पर उनकी थीसिस के लिए। हिल्टन–यंग कमीशन के समक्ष उनका साक्ष्य भारत में मुद्रा समस्या की चर्चा में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। विभिन्न अवसरों पर, उन्होंने भूमिहीन मजदूरों, छोटी जोत, खेती व्यवस्था, सामूहिक खेती, भू–राजस्व और जमींदारी उन्मूलन के मुददों को सम्बोधित किया है। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भोजन की स्थिति, समाजवाद और सामाजिक समानता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपने बजट भाषणों में उन्होंने कराधान की समस्याओं पर भी चर्चा की थी।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

हिन्दू कोड बिल तथा महिलाओं को सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार–अम्बेडकर को सिर्फ दलितों के लिए संघर्ष करने या भारतीय संविधान के निर्माण तक सीमित करने से उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। 1951 में कानून मंत्री के पद से अंबेडकर ने त्यागपत्र दलित के सवाल पर नहीं दिया था, बल्कि महिलाओं को संपत्ति में बराबरी के अधिकार के मुद्दे पर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सलाह–मशविरा करके उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें संपत्ति में महिला और पुरूष, दोनों के बराबर अधिकार का प्रावधान किया गया था। कई सांसदों ने जब इसका विरोध किया और वह बिल पास नहीं हो सका, तो अंबेड़कर बहुत आहत हुए और कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। क्या स्त्रीवाद की वकालत करने वाली महिलाओं ने अंबेड़कर के साथ न्याय किया? जो लोग स्त्री–पुरूष समानता की बातें करते नहीं थकते, क्या वे कभी इसकी चर्चा करते हैं? दलित महिलाओं को तो कुछ पता भी है, सवर्ण महिलाओं को तो नहीं के बराबर।

भारत राष्ट्र को बाबा साहब की देन–

- रोजगार कार्यालय की स्थापना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
- काम का समय 12 घण्टे से कम करके 8 घण्टा,
- महिलाओं को प्रसूति अवकाष, मंहगाई भत्ता,
- अवकाश का वेतन,
- हेल्थ इंश्योरेंस,
- कर्मचारी भविष्य निधि,
- श्रमिक कल्याण कोष,
- तकनीकी प्रषिक्षण योजना,
- सेंट्रल सिंचाई आयोग का गठन,
- वित्त आयोग का गठन
- मतदान का अधिकार,
- भारतीय सांख्यकीय कानून,
- हीराकुंड बाँध,
- दामोदर घाटी परियोजना,
- ओडिषा नदी परियोजना,
- भाखड़ा नांगल बाँध,
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना।

अम्बेडकर की दृश्टि में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं धर्म–आंबेडकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए समाजवाद को जरूरी मानते थे। आंबेडकर का समाजवाद सिर्फ आर्थिक समाजवाद नहीं था, सिर्फ आर्थिक समानता की बात नहीं करता, बल्कि वह सांस्कृतिक समानता की बात भी करता था। सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज में सांस्कृतिक रूप से जो असमानता और भेदभाव की खाई घर कर गई थी, जिसने समाज में असंतुलन पैदा कर दिया था, आंबेडकर उस असंतुलन को खत्म करने की बात करते हैं।

आंबेडकर जानते थे कि धर्म को समाज से और जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ आंबेडकर ने यह भी देखा था कि धर्म ने किस तरीके से एक राष्ट्र को बांट कर रख दिया था। ऐसी स्थिति में आंबेडकर संतुलन का एक नया रास्ता खोजकर निकालते है। वह धर्म का इस्तेमाल देश और समाज को विभाजित करने के लिए नहीं बल्कि उसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए करते है। वह कहते भी हैं कि धर्म मानव समाज की एकजुटता को मजबूत बनाने वाली शक्ति होना चाहिए। बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार अल्पसंख्यकों पर शासन करने का बहुसंख्यकों का ईश्वरीय अधिकार नहीं इस क्रम में वह धार्मिक राष्ट्रवाद के बजाय राष्ट्रवादी धार्मिकता पर बल देते है। (Ambedkar, BR, States and Minorities, What are their rights and how to secure them in the free Constitution of India, P. 52)

निष्कर्ष–आंबेडकर धर्म और राष्ट्र के बीच के बारीक संतुलन को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे उन्हें पता था कि धर्म का उफान असल में एक तरीके के जातीय अस्मिता को बल देता है जिससे राष्ट्रीय अस्मिता खंडित होगी इसलिए आंबेडकर धर्म को राष्ट्रीय चेतना से संबद्ध करने की वकालत करते हैं। वह मानते हैं कि राष्ट्रवाद, जातीय अस्मिता की भावना को खंडित करेगा और दरअसल राष्ट्रवाद ही वह सामाजिक युक्ति है जो सबको एक मंच पर खड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसलिए आंबेडकर संविधान तैयार करते समय धर्म की एक अपनी निश्चित भूमिका और राष्ट्र के संदर्भ में उसका

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अपना स्थान स्पष्ट कर देते हैं।

आंबेडकर के जीवन में जातिवाद का जहर घोलने वाले हजारों दुश्मन थे, किन्तु आपकी प्रतिभा, प्रबल इच्छा शक्ति एवं ओजस्वी विचारधारा के आगे दुश्मन सदैव नतमस्तक थे। डॉ0 आंबेडकर के विषय में हम कह सकते है कि यह संसार एक सौरमण्डल की तरह है और आप उस सौरमण्डल का सूर्य। डॉक्टर आंबेडकर धन्य हैं जिनके पास अदम्य साहस, हिमालय पर्वत के समान दृढ़ संकल्पित इरादे जिन्हें डगमगाने की इस दुनिया में किसी के पास साहस न था। आपके आगे पूरा विष्व नतमस्तक हो गया था। इसी असीम ज्ञान के कारण समस्त मानव जाति का प्रेरणास्रोत बन गये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रवेश कुमार : ''डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक– आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता'।
2. विप्लव राही : डॉ0 अम्बेडकर जयन्ती पर विशेष लेख (14 अप्रैल 2021) ''संविधान निर्माता ही नहीं दिग्गत अर्थशास्त्री भी थे डॉ0 अम्बेडकर।''
3. बाबा साहब अम्बेडकर 2013 तृतीय संस्करण : ''क्रांति और प्रतिक्रांति : बुद्ध अथवा कार्लमार्क्स आदि में नारी एवं प्रति क्रांति, सम्पूर्ण वांड्मय, खण्ड–7 डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली पृ0 335–336।
4. भीमराव अम्बेडकर 2009 'हिन्दू नारी का उत्थान और पतन', गौतम बुक सेंटर, दिल्ली पृ0–24 ।
5. (Ramesh Chand, 'Dr Ambedkar : Life and Mission' Yojna, May- 15-1991, P. 28)
6. डॉ0 विवेक आर्य– डॉ0 अम्बेडकर का राश्ट्रवादी चिंतन
7. E.A. Watter, (1963), The Cambridge History of the British Empire : South Africa. Rhodesia and the High Commission Territories, Cambridge University Press PP, 690-1
8. Report of the Royal Commission on Indian Currency and Finance. INDIAN CULTURE.

*****